बारिश से राहत मगर सब्जियों में उफान

बारिश कम होने पर राहत और बचाव अभियान में तेजी आई, फंसे पर्यटकों को निकालने की कोशिश जारी

संजीव मुखर्जी

देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से जान-माल को नुकसान होने के साथ ही देश में कारोबार पर भी बुरा असर पड़ा है। पिछले कुछ दिनों से देश के उत्तरी राज्यों हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो रही है।

इस बीच भारी बारिश के बीच दिल्ली में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी सब्जियों के दाम में भारी इजाफा हुआ है। कारोबारियों का कहना है कि बारिश थमने से पहले कीमतों में कमी आने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है क्योंकि सड़कें बंद हैं और खेत-खलिहानों और मैदान पानी से लबालब हैं। आजादपुर एपीएमसी के पूर्व सदस्य एवं सब्जी व्यापारी संघ के अध्यक्ष अनिल मल्होत्रा ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में खेतों में लगी सब्जियां डूब गई हैं। इससे बाजार में आपूर्ति कम हो गई है जिससे दाम काफी बढ़ गए हैं। सोनीपत, पानीपत जैसे इलाकों से भी सब्जियां बाजार में नहीं आ रही हैं। कई जगह ट्रक चालक आसपास के इलाकों में ही सब्जियां उतार कर बेच रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पहले केवल टमाटर की कीमतें बढ़ी थीं मगर पिछले कुछ दिनों में लगभग सभी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जियों के दाम में भारी तेजी और खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचने से खुदरा खाद्य महंगाई पर असर हुआ होगा। मई में यह कई महीनों के निचले स्तर 2.9 प्रतिशत पर आ गई थी। मैच्योर फार्म में प्रमुख, फार्म बिजनेस, तुषार त्रिवेदी कहते हैं कि भारी बारिश से सब्जियों के दामों में इजाफा हुआ है। इसके अलावा फसलों को हुए नुकसान और आपूर्त में बाधा आने से भी हालात सभी लिहाज से प्रतिकूल हो गए हैं। अगर कीमतें जल्द नीचे नहीं आई तो महंगाई दर में बढ़ोतरी होनी तय है।

क्रेड्यूस के एमडी एवं संस्थापक शैलेंद्र सिंह ने कहा कि अगर सब्जियों के दाम में इसी तरह बढ़ोतरी जारी रही तो लोग अपने खर्च पर लगाम लगा सकते हैं। क्रेड्यूस कार्बन कम करने की दिशा में काम करने वाली स्टार्टअप इकाई है। एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार खर्चों में कमी का सिलसिला शायद शुरू हो भी गया होगा। इस सर्वेक्षण में भाग लेने लगभग 75 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्होंने टमाटर का उपभोग कम कर दिया है। सात प्रतिशत लोगों ने कहा कि कीमतों के उछलने के साथ ही उन्होंने इसकी खरीदारी बंद कर दी थी। क्रिसिल के एक सर्वेक्षण के अनुसार दलहन की महंगाई दर अगले 6-7 महीनों के लिए और ऊंचे स्तरों पर रह सकती है। क्रिसिल के अनुसार असमान वर्षा से दलहन की बुआई पर असर हो रहा है।

दिल्ली में मंगलवार को यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण नदी किनारे बसे लोगों के घर डूब गए फोटो–पीटीआई

दिल्ली: लोगों को निकाला गया

राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को यमुना नदी का जलस्तर 206 मीटर के निशान को पार कर गया, जिससे बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का काम शुरू कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि एहतियातन पुराने रेलवे पुल को सड़क व रेल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं दिल्ली सरकार ने मंगलवार को बताया कि शहर में उफनती यमुना नदी के डूब क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी शिविरों में स्थानांतरित कर दिया गया है तथा उन्हें भोजन और पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि प्रभावित लोगों को स्थानांतरित किया जा रहा है, जहां उनके लिए 2,700 से अधिक तंबुओं की व्यवस्था की गई है।

बचाव अभियान में तेजी

उत्तर भारत के राजस्थान से लेकर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश तक लगातार हो रही बारिश मंगलवार को भी जारी रही, जिसके कारण सात और लोगों की मौत हो गई जबकि सैकड़ों लोग अभी भी इन क्षेत्रों में फंसे हुए हैं। प्रभावित राज्यों की सरकारों ने पिछले तीन दिन की लगातार बारिश के कारण हुई भारी तबाही के मद्देनजर प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेज कर दिए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण चार लोगों की मौत हुई जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई। हिमाचल प्रदेश अत्यधिक वर्षा से सबसे अधिक प्रभावित है, और यहां कम से कम 300 लोग फंसे हुए हैं।

कम बारिश से चीनी उत्पादन में गिरावट

इस साल गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्यों में कम बारिश से चीनी का कम उत्पादन होने का संकट खड़ा हो गया है। किसानों और उद्योग के सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि जिस वक्त गन्ने की फसल बढ़ती है उस वक्त उसे पर्याप्त बारिश की आवश्यकता पड़ती है, जो कि इस साल नहीं हुई।

महाराष्ट्र और कर्नाटक में इस साल चीनी का कम उत्पादन होगा। ये दो ऐसे राज्य हैं जहां देश का आधे से अधिक चीनी का उत्पादन होता है। इस कारण दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश निर्यात कम करेगा।

भारत का प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र के पश्चिमी जिले सातारा के किसान भरत संकपाल ने कहा, 'जून से सितंबर तक होने वाली भारी वर्षा से गन्ना फलता-फूलता है, लेकिन इस वर्ष कम वर्षा के कारण गन्ने की वृद्धि लगभग रुक गई है।' मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 1 जून से शुरू हुए इस मॉनसून सीजन में अब तक महाराष्ट्र के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिलों में सामान्य से 71 फीसदी कम बारिश हुई है।

पड़ोसी राज्य कर्नाटक, जो तीसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है, वहां गन्ना उगाने वाले जिलों में 55 फीसदी तक कम बारिश हुई है।

रॉयटर्स

मॉनसून के आगमन के साथ ही भारी बारिश के कारण बड़े कारोबारों पर भी असर हुआ है। एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रवक्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इसकी विनिर्माण इकाइयों में परिचालन पर थोड़ा असर हुआ है। प्रवक्ता ने कहा कि भारी बारिश की वजह से वाहनों की आवाजाही पर असर हुआ है जिसका असर उनके संयंत्रों में काम पर भी हुआ है।

वी-जॉन समूह के सीईओ विमल पांडे ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बद्दी में उसके संयंत्र ठीक ढंग से काम कर रहे हैं और परिचालन पर कोई असर नहीं हुआ है। पांडे ने कहा कि सभा कर्मचारी पहले की तरह फैक्टरी आ रहे हैं।

ईडी निदेशक का सेवा विस्तार अवैध: न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के तीसरे सेवा विस्तार को मंगलवार को अवैध करार दिया तथा उनका विस्तारित कार्यकाल घटाकर 31 जुलाई तक कर दिया। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल के पीठ ने कहा कि इस साल वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) द्वारा की जा रही संबंधित समीक्षा के मद्देनजर और सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक रहेगा।

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 1984-बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी का कार्यकाल 18 नवंबर, 2023 तक निर्धारित था। पीठ ने, हालांकि ईडी निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम पांच साल तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में संशोधन की पुष्टि की।

शीर्ष अदालत ने ईडी प्रमुख को दिए गए तीसरे सेवा विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आठ मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायालय ने इन याचिकाओं पर गत वर्ष 12 दिसंबर को केंद्र सरकार एवं अन्य से जवाब तलब किया था।

न्यायालय ने जया ठाकुर की याचिका पर केंद्र सरकार, केंद्रीय सतर्कता आयोग और ईडी निदेशक को नोटिस जारी किए थे। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और साकेत गोखले ने भी ईडी प्रमुख के सेवा विस्तार के खिलाफ याचिकाएं दायर की थीं। 62 वर्षीय मिश्रा को 19 नवंबर, 2018 को दो साल के लिए ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया था। बाद में, 13 नवंबर, 2020 के एक आदेश के जरिये केंद्र सरकार ने नियुक्ति पत्र को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया और दो साल का कार्यकाल बदलकर तीन साल कर दिया गया। सरकार ने पिछले साल एक अध्यादेश जारी किया था, जिसके तहत ईडी और सीबीआई) प्रमुखों को दो साल के अनिवार्य कार्यकाल के बाद तीन साल का सेवा विस्तार दिया जा सकता है।

न्यायालय का फैसला सरकार के मुंह पर तमाचा: कांग्रेस

कांग्रेस ने ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के तीसरे सेवा विस्तार को न्यायालय द्वारा अवैध करार दिए जाने के बाद मंगलवार को कहा कि यह उसके रुख की पुष्टि है और सरकार के 'मुंह पर तमाचा' है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार का यही मकसद था कि ईडी निदेशक को गैरकानूनी तरीकों से सेवा विस्तार दिया जाए। **भाषा**

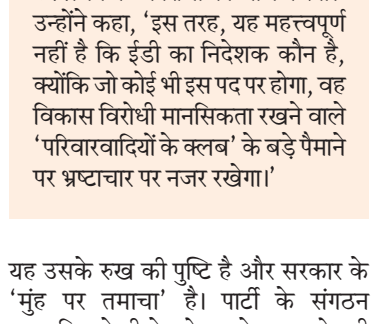

भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जारी रहेगी: शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि यह महत्त्वपूर्ण नहीं है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का निदेशक कौन है, क्योंकि जो कोई भी इस पद पर होगा, वह विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले परिवारवादियों के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर नजर रखेगा। शाह ने कहा, 'ईडी मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर खुशी मना रहे लोग विभिन्न कारणों से भ्रम में हैं। सीवीसी (केंद्रीय सतर्कता आयोग) अधिनियम में संशोधन, जिसे संसद द्वारा विधिवत पारित किया गया था, को बरकरार रखा गया है।' उन्होंने कहा कि भ्रष्ट और कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए ईडी की शक्तियां पहले जैसी हैं क्योंकि यह एक ऐसी संस्था है जो किसी व्यक्ति विशेष से परे है और यह अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रति लक्षित है, यानी धन शोधन और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के अपराधों की जांच करना।' उन्होंने कहा, 'इस तरह, यह महत्त्वपूर्ण नहीं है कि ईडी का निदेशक कौन है, क्योंकि जो कोई भी इस पद पर होगा, वह विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले 'परिवारवादियों के क्लब' के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर नजर रखेगा।'

दिल्ली–मुंबई में कंपनियां कर रहीं ज्यादा भर्ती

शिवानी शिंदे

पिछले छह महीनों में दिल्ली और फिर मुंबई में सबसे ज्यादा लोगों को नौकरियां मिली हैं। हालांकि, आंकड़े दर्शाते हैं कि कुछ क्षेत्रों में नियुक्तियां कम हुई हैं। नौकरी और पेशेवरों के नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के अध्ययन से यह खुलासा हुआ है।

अपना डॉट कंपनी के अनुसार, साल 2023 के पहले छह महीनों में दिल्ली में 70,000 नौकरियां थीं। कंपनी के प्लेटफॉर्म पर भी 25,000 नए नियोक्ता जुड़े हैं, जो पिछले साल की तुलना में 16.3 फीसदी की वृद्धि है।

दूरसंचार, सेल्स ऐंड मार्केटिंग जैसे उद्योगों ने हर पांच मिनट पर नौकरी की एक पोस्ट कर इस विकास को गति दी।

मुंबई दूसरा ऐसा शहर रहा जहां सबसे ज्यादा नौकरियां मिलीं। साल 2023 के पहले छह महीनों में अपना डॉट कंपनी पर 45 हजार नौकरियां थीं, जिनमें नई करियर संभावनाओं को तवज्जो दी गई। महाराष्ट्र की राजधानी में सेल्स ऐंड मार्केटिंग, वित्त और लेखा तथा मानव संसाधन और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में लोगों को भर्ती किया गया।

साल के शुरुआती छह महीनों में मुंबई में नए नियोक्ताओं की संख्या

में भी 30 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले साल की तुलना में करीब 10,000 नए नियोक्ता इस प्लेटफॉर्म से जुड़े।

अपना डॉट कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्याधिकारी निरमित पारिख ने कहा, 'नौकरी के अवसर में हुई वृद्धि जो हम देख रहे हैं वह नियोक्ताओं को उनकी भर्ती जरूरतो को पूरा करने में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम नियोक्ताओं और नौकरी की चाहत रखने वालों को समान अवसर देते हैं। उनके बीच की खाई को पाटने और समान अवसर देने के लिए समर्पित हैं।'

इस प्लेटफॉर्म ने मुंबई में सक्रिय रूप से नौकरी ढूंढ़ रहे करीब लगभग 2.5 लाख आवेदकों को आकर्षित किया है। कंपनी ने कहा कि कुल आवेदनों में लगभग 38 फीसदी महिलाएं शामिल थीं, जो कार्यबल में उनकी सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है।

15 साल में 41 करोड़ लोग गरीबी से उबरे

भारत में 2005-06 से 2019-2021 के दौरान सिर्फ 15 साल में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में मंगलवार को यह जानकारी दी गई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय में ऑक्सफर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (ओपीएचआई) द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश (भारत) ने गरीबी उन्मूलन के मोर्चे पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसमें कहा गया है कि भारत सहित दुनिया के 25 देशों ने पिछले 15 साल में सफलता के साथ अपने वैश्विक एमपीआई मूल्य को आधा किया है। इससे इन देशों में हुई प्रगति का पता चलता है। इन देशों में कंबोडिया, चीन, कॉन्गो, होंडुरास, भारत, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया और वियतनाम शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक, भारत ने अप्रैल में 142.86 करोड़ लोगों के साथ जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। अब भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। रिपोर्ट में कहा गया, 'विशेष रूप से भारत ने गरीबी उन्मूलन के मोर्चे पर

काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। सिर्फ 15 साल में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।' रिपोर्ट कहती है कि गरीबी में कमी लाना संभव है। कोविड-19 के महामारी के दौरान के व्यापक आंकड़ों की कमी की वजह से तात्कालिक संभावनाओं का आकलन करना थोड़ा मुश्किल है। भारत में 2005-06 से 2019-21 तक 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 2005-06 में भारत में लगभग 64.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी में थे। 2015-16 में यह संख्या घटकर लगभग 37 करोड़ पर और 2019-21 में 23 करोड़ पर आ गई।

रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में पोषण के संकेतक के आधार पर बहुआयामी गरीबी और वंचित लोगों की संख्या 2005-06 के 44.3 प्रतिशत से घटकर 2019-21 में 11.8 प्रतिशत पर आ गई। बाल मृत्यु दर भी इस दौरान 4.5 प्रतिशत से घटकर 1.5 प्रतिशत रह गई। **भाषा**

आज़ादी का अमृत महोत्सव

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

www.bankofbaroda.in

निविदा सूचना

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एंटी–मनी लॉन्ड्रिंग (AML) सोल्यूशंस की आपूर्ति, क्रियान्वयन और सपोर्ट के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है।

विस्तृत विवरण बैंक की वेबसाइट **www.bankofbaroda.in** के निविदा खंड और गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल पर उपलब्ध है।

"परिशिष्ट", यदि कोई हो, को बैंक की वेबसाइट पर **www.bankofbaroda.in** निविदा खंड में जारी किया जाएगा। प्रस्ताव को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले बोलीकर्ता इसे अवश्य देख लें ।

बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 02 अगस्त 2023 है।

स्थान: मुंबई
दिनांक: 12.07.2023 **मुख्य महाप्रबंधक (आईटी)**

56/23-24

SBI

कृपया ध्यान दें
भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक

बैंक ने ग्राहक के अधिकारों को शामिल करते हुए संशोधित/अनुपूरक लॉकर करार जारी किया है। भारतीय स्टेट बैंक से लॉकर सुविधा का लाभ उठाने वाले ग्राहकों से अनुरोध है कि वे अपनी लॉकर धारक शाखा से संपर्क करें और लागू संशोधित/अनुपूरक लॉकर करार निष्पादित करें।

Business Standard EV DIALOGUES

in association with CHARGE ZONE POWERING THE FUTURE BILLION

HIGHWAY TO GREEN GROWTH: ROLE OF EVs

July 18 Taj Mahal, New Delhi

Chief Guest
Nitin Gadkari
Union Minister for Road Transport & Highways

In a fireside chat with
Nivedita Mookerji
Executive Editor, Business Standard

Session 1
How to make EVs mainstream by 2030?

Session 2
Becoming *atmanirbhar* in EVs

Participation by invitation only
For invites, register at **bit.ly/bs-ev** or write to **lalit.saini@bsmail.in**

Co-sponsor LSI FINANCIAL SERVICES | PMI | Association Partner SMEV SOCIETY of MANUFACTURERS of ELECTRIC VEHICLES | Webcast Partner 24 FRAMES DIGITAL

Business Standard
Insight Out

business.standard bsindia business-standard.com